

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] No. 157]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 13, 2007/ज्येष्ठ 23, 1929 NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 13, 2007/JYAISTHA 23, 1929

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 5 जून, 2007

सं. **ई (ओ) III-84/पीएम 6/132.**—भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 16-7-1986 के समसंख्यक संकल्प में, जिसमें रेल मंत्रालय के अधीन 24,050-26000 रु. के वेतनमान में महाप्रबंधकों के पदों की नियुक्ति करने के लिए सिद्धांत और कार्यविधि दी गई है, भारत सरकार अनुबंध में यथोल्लिखित एक संशोधन करते हुए इस संकल्प को तत्काल प्रभाव से स्वीकार करती है।

मैथ्यू जॉन, सचिव

अनुबंध

रेल मंत्रालय के अधीन 24,050-26000 रु. के वेतनमान में महाप्रबंधकों के पदों पर नियुक्ति करने के लिए सिद्धांतों और कार्यविधि के संबंध में 16-7-1986 के संकल्प में संशोधन

दिनांक 16-7-1986 के संकल्प के अनुबंध में उल्लिखित महाप्रबंधकों के पदों पर नियुक्ति करने हेतु योजना के पैरा 7 (शीर्ष 'पात्रता मानदंड') के अंतर्गत, निम्नलिखित आशोधन किए जाएं :--

पैरा 7.2 में "विचार किए जाने हेतु प्रत्येक ऐसे अधिकारी को उस वर्ष, जिसमें चयन किया जाना है, में आए शब्द पहली जुलाई'' को संशोधित करके 'पहली अप्रैल' पढ़ा जाए :-

- "7.2 विचार किए जाने हेतु प्रत्येक ऐसे अधिकारी को उस वर्ष, जिसमें चयन किया जाना है, की पहली अप्रैल को":
- 2. इसके अतिरिक्त, 16-7-1986 के संकल्प के उक्त उपबंध के पैरा 9 में आए शीर्ष "चयन समिति की बैठक की आवधिकता और पैनल वर्ष" के अंतर्गत, मौजूदा पैरा को संशोधित करके नीचे दिए गए अनुसार पढ़ा जाए :-

''चयन सिमित सामान्यत:, पिछले वित्त वर्ष की 15 जुलाई और नवंबर के बीच उपयुक्त समय पर वर्ष में एक बार बैठक करेगी और उस वर्ष की मार्च तक की गोपनीय रिपोर्टों पर विचार करेगी। यदि परिस्थितिवश अपेक्षित हो, तो एक वर्ष से कम के अंतरालों पर भी बैठकों आयोजित की जा सकती हैं। वह वर्ष की 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक की अविध के दौरान महाप्रबंधकों और समकक्ष पदों पर मौजूदा और प्रत्याशित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए, उतने नाम जितने आवश्यक हैं, का एक पैनल तैयार करेगी। चयन सिमित द्वारा तैयार किया गया पैनल वर्ष की 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च की अविध के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए विधि मान्य होगा।"

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the 5th June, 2007

No. E (O) III-84/PM6/132.—In the Government of India, Ministry of Railways (Railways Board) Resolution of even number dated 16-7-1986 laying down principles and procedure for making appointment to the posts of General Managers in scale Rs. 24,050-26,000 under the Ministry of Railways, the Government of India adopts this Resolution introducing an amendment as indicated in the Annexure with immediate effect.

MATHEW JOHN, Secy.

ANNEXURE

Amendment to Resolution dated 16-7-1986 regarding Scheme for making appointment to the posts of General Managers in scale of Rs. 24,050-26,000 under the Ministry of Railways

Under the heading 'Eligibility Criteria' appearing in Para 7 of the Scheme for making appointment to the posts of General Managers indicated in Annexure to the Resolution dated 16.07.1986, the following modifications should be made:

The words "For being considered every such officer should on 1st July of the year in which selection is made" appearing in Para 7.2 shall be amended to read as:

- "7.2. For being considered every such officer should on 1st April of the year in which selection is made"
- 2. Further, under the heading "Periodicity of meeting of Selection Committee and the panel year" appearing in Para 9 of the said Annexure to the resolution dated 16-7-1986, the existing Para shall be amended to read as under:

"The Selection Committee shall normally meet once a year between 15th July and November of the preceding financial year and take into consideration the Confidential Reports upto March of that year. They may meet at intervals of less than a year, if the circumstances so require. They will draw up a panel, consisting of such number of names as may be necessary for appointment to the existing and anticipated vacancies in the posts of General Manager and equivalent during the period from 1st April of the year to 31st March of the next year. The panel drawn up by the Selection Committee shall be valid for vacancies arising during the period 1st April of the year to 31st March of the next year."